(घ) किन-किन राज्यों के बारे में ये शिकायतें मिली हैं कि उन्होंने जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित की गई निधियों का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार और अल्परोजगार वाले व्यक्तियों पुरूषों और महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाने के मुख्य उद्देश्य के साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी कार्यान्वित की जाती रहेगी । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम के लक्ष्यों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संशोधन तैयार किए जा रहे हैं ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष रोजगार सृजन (लाख श्रम दिनों में)

	लक्ष्य	उपलब्धियां
1989–90	8757.25	8643.87
1990–91	9291.04	8745.59
1991–92	7354.34	8126.20

(ग) इन तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष के दौरान अरूणोचल प्रदेश, गोवा जम्मू व कश्मीर कर्नाटक, मेघालय और पश्चिमी बंगाल ने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था ।

(घ) किसी भी राज्य ने जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटित निधियों का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया है ।

Intension sanitation project in Assam

4823. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will tne PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal regarding "Intensive Sanitation Project" in Kamrup district of Assam; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DAVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Yes, Madam.

(b) State Government of Assam had sent a proposal for Intensive Sanitation Project in Kamrup district at an estimated cost of Rs. 30.13 crore. The Central Government has accorded technical approval for implementation of the scheme in principle. Phase I of the scheme to be implemented in two years has been approved at an estimated cost of Rs. 441.31 lakhs. This involves construction of 21,000 household sanitary toilets and 63,000 other sanitary facilities at a total cost of Rs. 411.57 lakhs to be shared as follows:—

(Rs in lakhs)

—Assistance from United Nations Children Fund	30.40
—Central Government	30.40
—Government of Assam	30.48
—Beneficiary contribution	320.29
TOTAL :	411.57

THEUNICEF will also contribute a sum of Rs. 29.74 lakhs towards advocacy, training, administration and establishment charges.